SHORT NOTICE QUESTNON

देहरादून में चूने के पत्थर की खदानें

SNQ. 15. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**

क्या खान और ईंधन मंत्री २४ अप्रेल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को देहरादून के निकट पत्थर की खदानों के सम्बन्ध में, जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के नियंत्रण में है, कुछ अपीलें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार इन अपीलों का निर्णय करने के लिए कुछ निश्चय करने वाली है ; और

(ग) यदि हां, तो इन अपीलों पर कब तक निर्णय हो जायेगा ?

खान और ईंधन मन्त्री (के०दे० मालवीय): (क) ऐसा अनुमान है कि यह प्रश्न राज्य सरकार द्वारा दिये गये आदेशों के विरुद्ध पार्टियों द्वारा भेजे गये पुनरीक्षण प्रार्थना पत्रों से सम्बन्धित है। यदि यह ठीक, तो उत्तर स्वीकारात्मक है। १-१-१९५८ [illegible]रादून जिले में पाये जाने वाले चूना-पत्थर के लिए खनिज-रियायात से सम्बन्धित ऐसे ५६ पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुए।

(ख) जी हां। उच्च स्तर पर सभी पुनरीक्षण प्रार्थना पत्रों को निपटाने का इरादा है।

(ग) १९५८ से देहरादून में पाये जाने वाले चूना-पत्थर का खदानों से सम्बन्धित प्राप्त हुए ५६ पुनरीक्षण प्रार्थना पत्रों में से ४२ प्रार्थना-पत्रों का निपटारा किया जा चुका है और शेष १४ प्रार्थना पत्रों का निपटाद नहीं हुआ है। इन १४ प्राप्रार्थना पत्रों में से ८ प्रार्थना-पत्र १९६३ में, ३ प्रार्थना-पत्र १९६२ में, और शेष प्रार्थना-पत्र १९६०-६१ में प्राप्त हुए। अर्ध-नयाय पद्धति (quasi-judicial procedure) के अनुसार करने कि आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए उनके निपटाने के लिए समय-अवधि का निश्चय करन सम्भव नहीं है। फिर भी उनके निपटानमें शीघ्रता लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है।

12.5 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

COMPLAINTS MADE BY DETENUS TO INDIAN HIGH COMMISSION, CEYLON

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): I call the attention of the Prime Minister to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:—

The complaints made by persons of In[illegible]n origin in the Detention Camp in Slave Island, near Colombo, to the Indian High Commission in Colombo regarding the treatment meted out to them.

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh): Following the opening of an additional detention camp at Slave Island near Colombo, an official of the Indian High Commission in Colombo visited the camp on the 22nd April, 1963, to meet the persons of Indian origin detained there and to see what facilities were available to them. There were, at the time, a total of 186 persons detained at the camp, of which a majority were alleged illicit immigrants, the others being Indians arrested for overstaying their visas.

Some difficulties of the inmates about lack of accommodation and inadequacy of certain amenities which came to notice were subsequently brought to the notice of the Ceylonese authorities concerned, who have agreed to examine the points, immediately, and to do everything possible to improve the conditions.